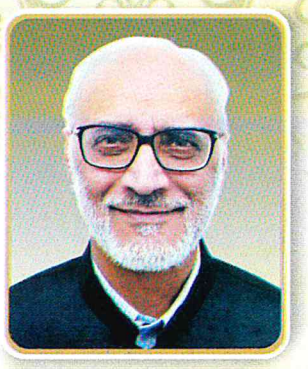

Prof. Ashok Gulati

Prof. Ashok Gulati is widely recognized in national and global circles as an authority on agricultural policy issues, particularly focused on India. He is currently Infosys Chair professor for Agriculture Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), a premier think tank based in Delhi.

2. Born on May 11, 1954, Prof. Gulati did his Masters and Ph.D from Delhi School of Economics, University of Delhi. He started his career as Lecturer in Desh Bandhu College and then moved to Shri Ram College of Commerce in University of Delhi. Soon he shifted his focus to agri-policy research and became Chief Economist in National Council of Applied Economic Research, NABARD Chair Professor in Institute of Economic Growth, and then Director in International Food Policy Research Institute (IFPRI, Washington, D.C.). He served in IFPRI for more than 10 years (2001-11), where he played a catalytic role in decentralizing IFPRI globally, and establishing an Asia office in Delhi, which he headed later as Director in Asia. This has helped in transforming the structure and course of this global organization for good, making it more valuable to various stakeholders, especially in developing countries.

3. Prof. Gulati became the Chairman of the Commission for Agricultural Cost and Prices (2011-14) in Government of India, a body responsible for recommending minimum support prices for 23 agri-commodities to the Government. He is well known for transforming the Commission into a vibrant organ of the Government, supported by robust research and lively discussions on issues in agri-food space, especially those related to price incentives, markets, and food security, including the National Food Security Act of 2013.

4. Prof. Gulati was the youngest member of the Prime Minister's Economic Advisory Council during the period of Shri Atal Bihari Vajpayee. He was also a member of the State Planning Board of Karnataka and a member of the Economic Advisory Council of the Chief Minister of Andhra Pradesh. He was invited to be a member of the High Level Committee to Reorient and Restructure the Food Corporation of India. He played an important role in showing how food security scenario in the country can be made pro-small farmers and pro-poor, at a much lower cost, saving the Government thousands of crores of rupees each year.

5. Prof. Gulati has to his credit more than 10 books related to various aspects of agriculture in Asian countries, focusing on India in particular, published by reputed publishers. He has also published widely in international and national journals on agricultural policy issues. He was made a Fellow of the National Academy of Agriculture Sciences; a member of the Global Agenda Council on Food and Nutrition Security of the World Economic Forum; a member of the international Food and Agriculture Trade Policy Council; and has also been awarded the 'Visionary Benefactor of Agriculture' by the Consortium of Indian Farmers Association.

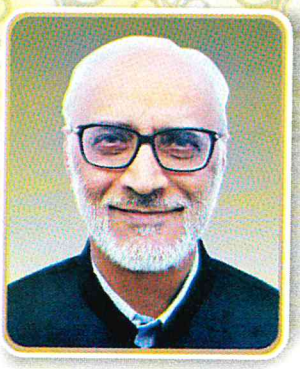

प्रो. अशोक गुलाटी

प्रो. अशोक गुलाटी, राष्ट्रीय और वैश्विक हलकों में विशेष रूप से भारत केंद्रित कृषि संबंधी नीतिगत मुद्दों पर एक सशक्त आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं। सम्प्रति आप दिल्ली में स्थित एक अग्रणी बौद्धिक संस्था, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधी भारतीय अनुसंधान परिषद में कृषि के इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर हैं।

4. आपका जन्म मई 11, 1954 को हुआ। आपने दिल्ली स्कूल ऑव इकॉनामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और पीएच.डी की डिग्री हासिल की। आपने अपने कॅरियर की शुरूआत देशबन्धु कॉलिज में व्याख्याता के तौर पर की, तत्पश्चात आप दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलिज ऑव कामर्स में चले गए। शीघ्र ही आपने अपना ध्यान कृषि संबंधी नीतिगत अनुसंधान की ओर लगाया तथा नेशनल काउंसिल ऑव अप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च में मुख्य अर्थशास्त्री, इंस्टीट्यूट इकॉनामिक ग्रोथ में नाबार्ड चेयर प्रोफेसर और उसके बाद इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आई एफ पी आर आई, वाशिंगटन, डी.सी.) में निदेशक बने। आपने आई एफ पी आर आई में 10 वर्षों से अधिक (2001-11) समय तक काम किया जहां आपने विश्वभर में आई एफ पी आर आई के विकेन्द्रीकरण तथा दिल्ली में एशिया कार्यालय स्थापित करवाने में अग्रणी भूमिका निभाई। आगे चलकर एशिया के निदेशक होकर इस कार्यालय के प्रमुख बने। इससे अच्छे परिणामों हेतु इस वैश्विक संस्थान की दशा और दिशा बदलने में सहायता मिली जिसके कारण यह विशेषकर विकासशील देशों में विभिन्न हितधारियों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सका।

3. आप सरकार को 23 कृषि-वस्तुओं के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य संस्तुत करने के लिए उत्तरदायी निकाय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारत सरकार के अध्यक्ष (2011-14) बने। आप आयोग को एक जीवंत निकाय में परिवर्तित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 सहित कृषि-खाद्य क्षेत्र, विशेषकर मूल्य प्रोत्साहन, बाज़ार और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर जबरदस्त अनुसंधान और फलदायी चर्चाओं के लिए जाने जाते हैं।

4. आप श्री अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। आप कर्नाटक राज्य योजना बोर्ड तथा मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश की आर्थिक सलाहकार परिषद के भी सदस्य रहे हैं। आपको भारतीय खाद्य निगम को फिर से नई दिशा देने तथा इसके पुनर्गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। आपने यह दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि किस प्रकार से देश की खाद्य सुरक्षा के परिदृश्य को बहुत ही कम लागत पर सीमान्त किसानों और गरीबों का हितैषी बनाया जा सकता है, जिससे सरकार को प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी।

5. आपको प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित एशियाई देशों विशेषकर भारत आधारित, कृषि के विभिन्न आयामों से संबंधित 10 से अधिक पुस्तकें लिखने का श्रेय जाता है। कृषि आधारित नीतिगत मुद्दों पर आपके लिखे लेख अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में व्यापक रूप से प्रकाशित हुए हैं। आपको राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी का फैलो; विश्व आर्थिक मंच की खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा संबंधी ग्लोबल एजेंडा काउंसिल का सदस्य; अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि व्यापार नीति परिषद का सदस्य बनाया गया तथा आपको कन्सोर्टियम ऑव इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा 'विजनरी बेनीफेक्टर ऑव एग्रीकल्चर' से भी सम्मानित किया गया है।